मानक आयुर्वेदिक औषधियां

9172. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जन साधारण को मानक आयुर्वेदिक औषधियां उपलब्ध कराने के लिए कोई केन्द्रीय आयुर्वेदिक फार्मेसी कार्यरत है और यदि हां, तो, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसी फार्मेसी स्थापित करने का है; और

(ग) इस समय राज्य सरकारों द्वारा कितनी आयुर्वेदिक फर्मेसियां चलाई जा रही हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार रानीखेत (उत्तर प्रदेश) में एक केन्द्रीय फार्मेसी खोल रही है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदीय और यूनानी पद्धतियों के औषधालयों और अन्य सरकारी संस्थाओं को इस पद्धतियों की पेटेंट और असली दवाइयां उचित दरों पर उपलब्ध की जा सकें । कुछ समय बाद ये दवाइयां आम जनता को भी उपलब्ध की जाएगी । प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्रों निगम की भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की केन्द्रीय फार्मेसी के प्रबन्ध हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीकृत करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।

(ग राज्य सरकारें 26 आयुर्वेदीय फार्मेसियां चला रही हैं ।

Implementation of E.P.F. Scheme in Bidi Factories, Karnataka

9173. SHRI RAJSHEKHAR KOLUR: Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS AND LABOUR be pleased to state:

(a) whether Employees' Provident Fund Scheme is implemented in the Bidi Factories in Gulbarga District, Karnataka;

(b) whether this scheme has shown successful results and is advantageous to workers; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (DR. RAM KIRPAL SINHA): (a) to (c). The Provident Fund authorities have reported as under:—

Of the 12 Bidi manufacturing establishments covered under the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 in Gulbarga District, Karnataka, 11 have remitted the provident fund dues. Against the remaining one establishment, suitable action under the Act has been initiated to secure compliance.

इंदौर में कर्मचारी भविष्य निधि के कार्यालय तथा कर्मचारियों के क्वार्टरों का निर्माण

9174. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में इन्दौर में कर्मचारी भविष्य निधि के कार्यालय के लिए एक इमारत तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के निर्माण पर लगभग 50 लाख रुपये खर्च किये गये थे किन्तु कार्यालय के लिए बनी इमारत खाली पड़ी है क्योंकि कुछ व्यक्तियों की गलती से कुछ गम्भीर